उत्तराखंड के राज्य बजट का विश्लेषण

द्वारा

एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर)
और
नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्लू)

नवंबर 2011

Data in this Kit is presented in good faith, with an intention to inform voters. Candidates' affidavit with nomination papers is the source of this analysis. www.adrindia.org, www.myneta.info

प्रस्तावना

उत्तराखंड को पहाडी प्रदेश होने से विशेष दर्जा प्राप्त है क्योंकि वहां अधिसंरचनात्मक और कार्य–संपादन खर्चों के साथ–साथ अभिशासन व्यय अधिक है। इस कारण उत्तरखंड को विशेष सुविधाएं मिली हुई हैं जिसके अंतर्गत केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के अनुपात मिलना शामिल है जबकि अन्य राज्यों को जिन्हें विशेष दर्जा नहीं मिला, केन्द्रीय सहायता 70 प्रतिशत अनुदान और 30 प्रतिशत ऋण के अनुपात में मिलती है।

प्रमुख वित्तीय संकेतक

उत्तराखंड के राज्य–बजट में 2005 से 2010 के बीच के प्रमुख वित्तीय संकेतकों का सार–संक्षेप तालिका–1 में दिया गया है। जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय बिन्दु हैं :–

- करेतर–राजस्व मद में कम वसूली होने से वर्ष 2009–10 के दौरान 13 प्रतिशत कम राजस्व आमदनी हुई। राज्य सरकार ने अपनी मध्यवर्ती नीति–वक्तव्य में राजस्व वसूली में कमी के लिए आर्थिक मंदी और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद उत्पन्न 2500 करोड रुपए की वित्तीय बोझ को जिम्मेवार ठहराया।
- शिक्षा, ग्रामीण विकास और सिंचाई क्षेत्र पर कम व्यय होने से वर्ष 2007–10 में पूंजीगत व्यय 16 प्रतिशत कम हुआ।
- पिछले पांच वर्षों से राजस्व घाटे और वित्तीय घाटे के बारे में बजट अनुमानों को उपलब्ध नहीं किया जा सका। वित्तीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 2005 द्वारा निर्धारित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के चार प्रतिशत वित्तीय घाटा का लक्ष्य राज्य ने वर्ष 2009–10 में उपलब्ध नहीं किया, वह 5.94 प्रतिशत रहा।

तालिका –1 : उत्तराखंड के वित्तीय संकेतक

सभी आंकडे करोड रु. में	2005.06	2006.07	2007.08	2008.09	2009.10
राजस्व आमदनी	5,537	7,373	7,891	8,635	9,486
राजस्व व्यय	5,610	6,476	7,254	8,394	10,567
राजस्व घाटा	–73	897	637	241	–1,081
पूंजीगत लेखा प्राप्ति	1,793	1,248	1,466	1,598	1,747
पूंजीगत व्यय	1,705	1,699	2,235	2,016	1,647
वित्तीय घाटा	–1,878	–885	–1,744	–1,843	–2,783

राजस्व प्राप्ति

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण तालिका 2 में दिया गया है जो बताती है कि राज्य की राजस्व आमदनी का 50 प्रतिशत से अधिक भारत सरकार के अनुदान या केन्द्रीय करों में हिस्से के रूप में केन्द्रीय स्रोतों से मिलता है ।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय कोष का बडा हिस्सा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे प्रदान कर रही है। इन कोषों को राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से नहीं भेजा जा रहा है।

तालिका 2 : राजस्व प्राप्तियों का विवरण

सभी आंकडे करोड रु. में	2005.06	2006.07	2007.08	2008.09	2009.10
कुल राजस्व आमदनी	5,537	7,373	7,891	8,635	9,486
राज्य का कर राजस्व	1,785	2,514	2,739	3,045	3,559
राज्य का करेतर राजस्व	650	647	668	699	632
केन्द्रीय करों में हिस्सा	1,010	1,132	1,428	1,506	1,550
भारत सरकार से अनुदान	2,092	3,081	3,056	3,384	3,745
केन्द्रीय स्रोतों से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	56 प्रतिशत	57 प्रतिशत	57 प्रतिशत	57 प्रतिशत	56 प्रतिशत

वचनबद्ध व्यय

राज्य के वचनबद्ध व्यय का लेखाजोखा उसके राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में तालिका 3 में दिया गया है। वचनबद्ध परिव्यय की परिभाषा लेखा–नियंत्रक सह आंकेक्षक ने ब्याज की अदायगी, वेतन और भत्ते, पेंशन और आर्थिक सहायता आदि पर होने वाले खर्चो के रूप में किया है। उल्लेखनीय बिन्दु निम्नलिखित हैं :–

- वेतन, पेंशन और ब्याज अदायगी को मिलाकर वर्ष 2009–10 में सरकार के कुल राजस्व खर्च का 71 प्रतिशत खर्च हुआ जिससे समाज–कल्याण की नई योजनाओं के लिए काफी कम (2424 करोड रु) रकम बच पाई। यह रकम प्रति व्यक्ति 2500 रु. से भी कम है।
- बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कुल राजस्व व्यय का 35 प्रतिशत से कम व्यय वेतन पर होना चाहिए जबकि वर्ष 2009–2010 में वेतन पर वास्तविक व्यय 53 प्रतिशत हुआ।
- छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से वर्ष 2008–09 से 2009–10 के बीच वेतन पर व्यय 44 प्रतिशत बढ गया।
-

तालिका 3 : उत्तराखंड के वचनबद्ध व्यय

सभी आंकडे करोड रु. में	2005.06	2006.07	2007.08	2008.09	2009.10
वेतन और भत्ते	1,381	1,551	2,232	3,045	4,388
ब्याज अदायगी	808	964	1,096	1,188	1,338
पेंशन	453	527	623	828	1,047
आर्थिक सहायता	–	–	–	42	42
अन्य घटक	1,549	1,858	1,470	1,117	1,543
कुल	4,191	4,900	5,421	6,220	8,358
राजस्व आमदनी का प्रतिशत	**76 प्रतिशत**	**66 प्रतिशत**	**69 प्रतिशत**	**72 प्रतिशत**	**88 प्रतिशत**

परिशिष्ट

परिभाषाएं

शब्द	परिभाषा
राजस्व प्राप्ति	राजस्व प्रप्ति में राज्य करों से प्राप्ति, राज्य की करेतर प्राप्तियां, केन्द्रीय करों में हिस्सा और भारत सरकार के अनुदान का कुल योग शामिल होता है।
पूंजीगत प्राप्ति	पूंजीगत प्राप्तियों में ऋण और अन्य देनदारियों के साथ ऋणों की वसूली शामिल होती है। पूंजीगत प्राप्तियों से देनदारी उत्पन्न होती है या संपत्तियों में कमी आती है।
राजस्व व्यय	ऐसे व्यय जिनसे दीर्घकालीन संपत्तियों का निर्माण नहीं होता, बल्कि सरकार के रोजमर्रा के कामकाज को चलाने में होते हैं।
पूंजीगत व्यय	परिचालन गत व्ययों के अतिरिक्त कोई व्यय जिसका लाभ एक वर्ष से अधिक समय तक मिलता है। यह संपत्ति के निर्माण पर होने वाला व्यय है।
राजस्व घाटा	राजस्व घाटा से राजस्व प्रापित और राजस्व व्यय के बीच के अंतर का पता चलता है।
सकल वित्तीय घाटा	वित्तीय घाटा कुल संचित रकम है जो सरकार की प्राप्तियों से अधिक व्यय का सूचक है। इसकी परिभाषा सीएजी ने राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, शुध्द ऋण और अग्रीम के योग से राजस्व प्राप्ति और विभिन्न मदों में पूंजीगत प्राप्तियों को घटाने के रूप में की है।
शुद्ध वित्तीय घाटा	सकल वित्तीय घाटा से केन्द्रीय ऋणों को निकाल देने पर प्राप्त रकम ।
योजना व्यय	योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त कार्यक्रमों/परियोजनाओं पर हुए व्यय
गैर–योजना व्यय	योजना से बाहर के सभी सरकारी व्यय, जिसमें मुख्य रूप से ब्याज अदायगी और आर्थिक सहायता पर हुए व्यय शामिल होते हैं।

Data in this Kit is presented in good faith, with an intention to inform voters. Candidates' affidavit with nomination papers is the source of this analysis. www.adrindia.org, www.myneta.info